और... एक शेर

ग़म की तौहीन न कर ग़म की शिकायत करके
दिल रहे या न रहे अज़मत-ए-ग़म रहने दे

-क़मर मुरादाबादी

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है जो सहायता करने की भावना रखता है. ■ अब्राहम लिंकन

संपादकीय

आतंकवाद से निपटने आक्रामक रुख अपनाएं

इराक, सीरिया समेत मध्य पूर्व के कई देशों में खूनखराबा कर रहे इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने वर्ष 2020 तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ दुनिया के बड़े इलाके में कब्जा करने का मंसूबा बनाया है. आतंकी संगठन पर एंड्रयू होसकेन की नई किताब 'द एंपायर ऑफ फीयर' के मानचित्र में मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रीका, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप का कुछ हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर आईएसआईएस अपनी हुकूमत जमाना चाहता है. इस्लामिक स्टेट पर एक नई किताब में दिए एक नक्शे के मुताबिक इस दुर्दांत आतंकी संगठन की योजना दुनिया के बड़े हिस्से में अगले पांच साल में अपना प्रभुत्व कायम करने की है, जिसमें लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है. पहली नजर में भले ही यह मंसूबा शेखचिल्ली के सपने की तरह मालूम पड़ता हो, लेकिन इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आईएसआईएस के मनोवैज्ञानिक असर से इराक और सीरिया के बाहर, भारत भी अछूता नहीं है. इस दुर्दांत आतंकी गिरोह की भारत में कोई पैठ हो पाई है, इसके पुख्ता सबूत तो नहीं हैं, लेकिन हाल ही में कश्मीर में इस संगठन का झंडा लहराने और देश के कुछ भागों से युवाओं के सीरिया जाने की खबरों से सुरक्षा एजेंसियां अवश्य अलर्ट हो गई हैं. ये खतरे के संकेत हैं. खतरा कम हो या ज्यादा, सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था तो करनी ही चाहिए. खतरा भले ही फौरी तौर पर न हो पर हमें सावधान तो रहना होगा. आतंक को लेकर अमेरिका और चीन की लड़ाई खुद के हितों को ध्यान में रखकर चल रही है. जहां तक भारत का सवाल है, वह आतंकवाद के मामले में अब तक डिफेंसिव मोड (सुरक्षात्मक रुख) में ही है. हम दुर्घटना होने के बाद उसके कारणों को ढूंढ़ते हैं. अब आवश्यकता एग्रेसिव मोड (आक्रामक रुख) में आने की है. इसके लिए इजराइल से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है जिसके विमान का फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा 1976 में एंटेब (युगांडा) विमानतल पर अपहरण कर लिया गया था. इजराइली कमांडो दल ने करीब ढाई हजार मील का सफर तय कर, युगांडा पहुंच कर अपहर्ताओं के चंगुल से 100 लोगों को बचाया और दुनिया को हैरत में डाल दिया. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में अपनी इस कार्रवाई का बेधड़क समर्थन करते हुए इजराइली रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि वे यात्री भी हमारे सैनिकों की तरह ही हैं. दुर्भाग्य से भारत में आतंक के खिलाफ लड़ाई का ऐसा आक्रामक जज्बा नजर नहीं आ रहा है. वहां देश की सुरक्षा के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष एक हो जाता है, हमें भी आतंकवाद के खिलाफ दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा. भारत की आंतरिक सुरक्षा पूरी निष्पक्षता के साथ सुदृढ़ करनी ही होगी. सीमाओं पर कंटीले तार तो हैं पर उनके उस पार से यदि किसी दुश्मन की बदनजर इस ओर पड़े तो वह हमारी बंदूक की जद में आनी ही चाहिए. मुंबई हमलों के बाद निश्चित ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आशंकित घुसपैठ को रोकने में पहले से ज्यादा सक्षम हुई हैं. फिर भी इस समस्या के निदान में उनके साथ-साथ सरकार और दूसरी संस्थाओं को भी हरकत में रहना चाहिए. इस बात को लेकर भी सजगता बढ़नी चाहिए कि सामाजिक स्तर पर डर और अलगाव न पनपे. ■■

पथ प्रदर्शक

''अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू या तंबाकू से बने पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है.'' शहर में पान की दुकानों पर यह तख्ती लगी थी. स्कूल के छोकरे सिगरेट पीना चाह रहे थे.

लघुकथा

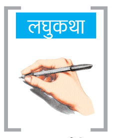

अंजु दुआ जैमिनी

''ओए, जा ले आ सिगरेट.''

''मैं नहीं जाता. पान वाला नहीं देगा.''

''अरे, कह देना पापा ने मंगाई है.''

लड़का दुकान जाकर बोला, ''भइया, एक सिगरेट का पैकेट देना. हां, गुटखा भी.''

''बच्चे, तुम तो बहुत छोटे हो. तुम्हें नहीं मिल सकता.''

''अंकल, मेरे पापा ने मंगवाई है. ये लो पैसे.''

''ओह! तुम तो वर्मा साब के बेटे हो.''

पानवाले ने सहर्ष उसे सामान दे दिया.

कुछ दिन बाद.....

''राम-राम वर्मा साब.''

''लीजिए साब. आजकल बेटे से बहुत सिगरेट मंगाने लगे हो. हर रोज शाम को आ जाता है.''

सुनकर वर्मा साब के हाथ से सिगरेट छूट गई. ■■

राजनीतिक दंगल में जंगल के दांव

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

समाज का एक बड़ा वर्ग राजनीतिक दंगल के सारे नियम-कानून-परंपरा टूटने तथा जंगल में होने वाले पारस्परिक अप्रत्याशित हमलों की तरह राजनीतिक दांव-पेंच देखकर विचलित हो रहा है. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर शहर के मेयर और गांव के सरपंच तक से सामान्य जन की अपेक्षा यही होती है कि वह सामाजिक मानदंड तय करने वाले हैं. महत्वपूर्ण शीर्ष पदों पर पहुंचकर वह पारस्परिक सद्भाव बढ़ाकर सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. नेहरू से अटलजी तक प्रधानमंत्रियों ने चुनावी रैलियों अथवा अपनी पार्टियों के सम्मेलनों में भी वैचारिक आधार पर विरोधियों की तीखी आलोचना की, लच्छेदार मुहावरों का इस्तेमाल किया और लाखों-करोड़ों लोगों को प्रभावित किया. लेकिन उनके उद्गारों में जहरीली निजी कटुता कभी नहीं झलकी. प्रतिपक्ष की पार्टियों को चुनाव में पराजित करने के प्रयास हुए, लेकिन उनके 'नाम-निशान' मिटाने के आह्वान नहीं हुए. पिछले कुछ अर्से से सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों के नेताओं ने ही नहीं, धर्म के कथित स्वामियों-साध्वियों ने भी अमर्यादित उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. भड़काऊ भाषणों का असर तत्काल भले ही न हो, लेकिन वह धीमे जहर की तरह समाज को अराजकता की ओर ले जा सकता है. संचार क्रांति के युग में आरोप-प्रत्यारोप के विषैले तीर मिनटों में दुनिया भर में पहुंच जाते हैं.

वाक् अग्निबाणों से कल्याण की वर्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अन्ना हजारे के गांधीवादी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने तो 'आम आदमी पार्टी' के अराजक रहने की घोषणा कर रखी है. भाजपा और कांग्रेस की गलतियों की सजा जनता ने दे दी

सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों के नेताओं ने ही नहीं, धर्म के कथित स्वामियों-साध्वियों ने भी अमर्यादित उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.

और 'आप' सत्ता में आ गई. लेकिन केजरीवाल के अहंकारी तेवर केंद्र सरकार के अति आत्मविश्वासी तेवरों से अधिक खतरनाक व संपूर्ण व्यवस्था विरोधी हैं. 'आप' के अधिकांश नेता अपने ढंग से नियम-कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं और माओवादी संगठनों की तरह अपनी 'पार्टी अदालतों' में फैसले करने लगे हैं. उन के जवाब में भाजपा के भी कुछ नेता अपराधी गिरोह के अगुआ की तरह लाठी-डंडे से मारपीट कर लाशें बिछा देने, विरोधियों को स्ट्रेचर पर भेजने जैसी धमकियां दे रहे हैं. यह कैसी लोकतांत्रिक लड़ाई है? लोकतांत्रिक छोटे अफ्रीकी देशों में भी ऐसे संघर्ष देखने को नहीं मिलते. विकसित लोकतांत्रिक देशों में तो चुनावी जय-पराजय के बाद विरोधी नेता को सरकार में शामिल करने तक की पहल होती है. सुरक्षा से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर तो वहां व्यापक सहमति रहती है. भारत का हाल देखिए- व्यापमं अथवा ललित मोदी घोटालों पर सत्ता तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव के कारण समझे जा सकते हैं. लेकिन गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बाद यदि प्रधानमंत्री स्वयं फोन से सोनिया गांधी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सीताराम येचुरी जैसे प्रतिपक्षी नेताओं से बात करके संसद में आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर वक्तव्य तथा प्रस्ताव के लिए समर्थन मांग लेते तो क्या कुछ घंटों के लिए संसद सुचारु रूप से नहीं चल सकती थी? अगले दिन प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में गृहमंत्री के माध्यम से लोकसभा में सरकार का वक्तव्य होना क्या लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है? महत्वपूर्ण और गंभीर विवादास्पद विषयों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति तथा हस्तक्षेप की अपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए?

इंदिरा गांधी 1971 के भारी जन समर्थन के बाद भी संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों में बहुत समय देने के साथ भूपेश गुप्ता, पीलू मोदी, राजनारायण, मधु लिमये, मधु दंडवते, अटलबिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी जैसे नेताओं के तीखे आलोचक भाषण धैर्यपूर्वक सुनती-सहन करती थीं. अटलबिहारी वाजपेयी भी आलोचना सुनने के बाद अपने चुटीले अंदाज में जवाब देते और बाद में केंद्रीय कक्ष तथा अन्य अवसरों पर प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बेहद स्नेहिल और सम्मानजनक व्यवहार करते रहे. गठबंधन के दौर में तो राजनीतिक असहमतियों वाले नेता अटल, आडवाणी, जार्ज फर्नांडीस, शरद यादव, जयललिता, मायावती, चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टियों ने एक साथ चलने की कोशिश की. कांग्रेस गठबंधन के दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों, द्रमुक और समाजवादी पार्टी ने सरकार का साथ दिया तथा राज्यों में सहयोग लिया. लोकतंत्र में एकदलीय सार्वदेशिक सत्ता को लक्ष्य कैसे बनाया जा सकता है? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, जयललिता अथवा तीन दशकों तक बंगाल में राज करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की संभावना तथा औचित्य से इंकार नहीं कर सकते हैं. स्वस्थ लोकतंत्र में असहमतियों की आवाज जरूरी है. नए राजनीतिक दौर में बेहद उत्तेजक तथा हिंसक वक्तव्यों और टिप्पणियों के मीडिया पर सीधे प्रसारण, सोशल मीडिया से घर-घर पहुंचने की स्थिति के खतरों पर भी विचार की जरूरत है. इस लक्ष्मण-रेखा के बाद का रास्ता दावानल का है. ■■

संसद : काम नहीं तो वेतन नहीं

कुलदीप नैयर
जाने-माने स्तंभकार

करीब 12 साल पहले मैं राज्यसभा का सदस्य था. किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन के कामकाज में बाधा पैदा की जाती थी. छह साल के अपने कार्यकाल में मैंने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों इसके लिए एक-दूसरे से होड़ लेते रहते थे. उनके जोश या तरीके में कोई अंतर नहीं था. कई बार वे एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे.

मुझे बहुत महसूस होता था कि हम सदस्यगण लोगों के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पहले से निराश लोगों को और निराश कर रहे हैं. इसलिए यह सवाल था कि क्या बतौर सांसद हमें सभी भत्ते लेने चाहिए. खासकर उस समय जब हमने कोई भी कामकाज नहीं किया हो. मैंने सभापति को पत्र लिखा कि जिस दिन सदन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के स्थगित हो जाए तो मैं भत्ता नहीं लेना चाहता हूं. कुछ सदस्यों की राय से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि वे 'काम' कर रहे हैं क्योंकि दिन के आखिर में सदन का सचिवालय दिन भर की कार्यवाही के सार को प्रस्तुत करने के लिए बुलेटिन निकालता है.

अगर कोई कामकाज नहीं होता है तो बुलेटिन भी यही बताता है. सभापति ने मेरी अर्जी को कानून मंत्रालय को भेज दिया क्योंकि ऐसा मामला पहले कभी नहीं आया था. कानून मंत्रालय ने मेरी दलील को सही माना. रोज के भत्ते में से उस दिन का मेरा भत्ता काट लिया जाता था जिस दिन सदन में कोई कामकाज नहीं होता था. सभापति ने सदन की कामकाज समिति को भत्ता काटने की जानकारी दी. किसी भी पार्टी, जिसमें वामपंथी भी शामिल थे, ने इस विचार से सहमति नहीं जाहिर की और इसे सदस्यों की अपनी इच्छा पर छोड़ दिया. मैंने कानून मंत्रालय की राय को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पास भेज दिया. मुझे लगता है, उन्होंने इसे कामकाज समिति के सामने रखा लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया.

मैं उम्मीद करता हूं कि 25 सदस्य, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने निलंबित कर दिया था, स्पीकर से पत्र लिखकर कहेंगे कि वे रोजाना भत्ते के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सदन में मौजूद नहीं थे. अगर यह रिवाज बन जाता है तो सदस्य पूरी तरह बेलगाम नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा अनुशासित होंगे. जब से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने लगा है, सदस्यों का पहनावा बेहतर हुआ है.

मैंने लोगों के सामने अपना उदाहरण इसलिए रखा कि बता सकूं कि मिसाल पहले से मौजूद है. सांसद अपने-अपने अंदर झांककर देखें कि क्या रोजाना भत्ता लेना उनके लिए सही है, जब उन्होंने जरा भी काम न किया हो. फिर भी, यह उस बड़े सवाल का जवाब नहीं देता, संसद के काम

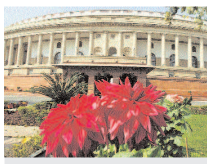

सांसद अपने-अपने अंदर झांककर देखें कि क्या रोजाना भत्ता लेना उनके लिए सही है, जब उन्होंने जरा भी काम न किया हो.

करने का तरीका. कांग्रेस ने ठान लिया है कि वह सत्र को चलने नहीं देगी जब तक सुषमा स्वराज और राजस्थान व मध्यप्रदेश के 'भ्रष्ट मुख्यमंत्री' पद नहीं छोड़ते.

कांग्रेस की मांग कितनी भी वजनदार क्यों न हो, आरोपों को पुष्ट करने के लिए एक मुकम्मल जांच की जरूरत है. सुषमा स्वराज के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग उचित नहीं है. उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अपने विवेक के दुरुपयोग का आरोप है कि उन्होंने कानून के भगोड़े ललित मोदी को, कैंसर से पीड़ित पत्नी को देखने के लिए पुर्तगाल जाने की इजाजत दी. इसमें पैसे का कोई मामला नहीं है. इसे भ्रष्टाचार का मामला बनाना अनुचित है.

बड़ा सवाल संसद के सत्र का है. कांग्रेस अपना बचाव यह कहकर कर रही है कि वह वही कर रही है जो भाजपा करती रही है. यह न तो नैतिक रूप से उचित है और न ही बौद्धिक रूप से सही. एक गलती दूसरी गलती को सही नहीं कर देती. ■■

गंगा की डॉल्फिनों को बचाने की तैयारी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को बचाने के उपाय तेज होते लग रहे हैं. फिलहाल गंगा में कई स्थलों पर पानी की कमी, जल-प्रदूषण और शिकार के

गंगा में कई स्थलों पर पानी की कमी, जल-प्रदूषण और शिकार के चलते डॉल्फिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. कमोबेश यही स्थिति चंबल में रहने वाली डॉल्फिन की है.

चलते डॉल्फिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. कमोबेश यही स्थिति चंबल में रहने वाली डॉल्फिन की है. डॉल्फिन राष्ट्रीय जल-जीव है किंतु इसके घरौंदे गंगा-चंबल सहित इनकी सभी सहायक नदियों में उजड़ते जा रहे हैं. देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान वनीकरण, जैविक विकरण और जैविक शुद्धिकरण के जरिए गंगा के पुनरुद्धार की बड़ी योजना बना रहा है. हालांकि योजना के अमल के बाद इसके परिणाम कितने सार्थक निकलेंगे, यह तो आनेवाला कल ही तय करेगा.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं, उन्हें गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है. वैसे डॉल्फिन गंगा की सहायक नदी घाघरा में भी पाई जाती है. 1982 में इनकी संख्या करीब पांच हजार थी, जो 2005 में घटकर 1600 रह गई. अक्तूबर 2012 में जब इनकी गिनती हुई तो इनका कुनबा महज 67 की संख्या में सिमट गया. तय है, डॉल्फिन का यह हश्र अवैध शिकार के चलते हुआ. यही हश्र चंबल और ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों का हो रहा है.

परंपरागत शिकारी आज भी डॉल्फिन को जाल बिछाकर ही गिरफ्त में लेते हैं. जाल में फंसने के साथ ही ये छूटने के लिए फड़फड़ाती हैं और आखिरकार दम तोड़ देती हैं. चंबल सफारी अभयारण्य में पर्यटकों को लुभाने के लिए जब से वन विभाग ने इसका प्रचार शुरू किया है, तब से डॉल्फिन को मारे जाने का आंकड़ा भी बढ़ा है. चंबल सफारी में जहां-जहां डॉल्फिन सरलता से देखने में आती है, वहां-वहां सचित्र सूचना-पटल लगाकर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है. जबकि इन विशेष स्थानों पर डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए न तो वनरक्षक तैनात हैं, न ही सुरक्षा के अन्य कोई इंतजाम हैं. लिहाजा, सफारी में सैलानियों का आमंत्रण इनकी मौत का सुगम कारण भी बन रहा है. ऐसे स्थलों पर आसान पहुंच मार्ग बनाकर भी वन अमले ने शिकार का रास्ता साफ कर दिया है. गंगा डॉल्फिन को बचाने के उपायों में इस तरह के तरीकों से बचने की जरूरत है. ■■

नजर के पार

'अर्जुन' की खामियां दूर करने की दरकार

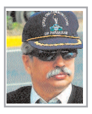

सारंग थत्ते
सेवानिवृत्त कर्नल

अर्जुन टैंक के भारी भरकम वजन- कुल मिलाकर 62 टन वजन ने इसे एक सफेद हाथी की संज्ञा दे दी है. वजनदार होने की वजह से इसकी चाल एक मुख्य युद्धक टैंक के अनुरूप मेल नहीं खाती. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 1972 में इसकी रूपरेखा को कागज पर उतारा था. 1996 में इसे हैवी व्हीकल फैक्टरी आवड़ी में बनाने की मंजूरी सरकार ने दी थी. 2004 में इसे सेना को देना शुरू किया गया. कुल 122 अर्जुन मार्क-1 फिलहाल सेना के खेमे में मौजूद हैं. इसमें मौजूद कई कमियों को बीते सालों में दूर किया गया लेकिन अब भी सेना में मौजूद ये टैंक फिलहाल कमजोर हालत में अपनी किस्मत को रो रहे हैं. जबसे इन्हें सेना ने अपनी दो यूनिटों में शामिल किया है, इनमें कमियां महसूस की गई हैं और जमीनी हालत यह है कि सेना इन सफेद हाथियों से खुश नहीं है.

इतने वर्षों की मेहनत के बाद भारतीय सेना ने अर्जुन की अगली खेप का अपना नया ऑर्डर रोक रखा है. इसका मुख्य कारण है कि अर्जुन मार्क-1 में मौजूद कमियों की जब गिनती की गई तो ये 73 तक जा पहुंचीं, जिसमें से 19 ऐसी कमियां थीं, जो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की मांग कर रही हैं. इन कमियों को दूर करने की सिफारिश सीएजी ने भी की थी जिसके चलते सीएजी के अनुसार अर्जुन टैंक फिलहाल युद्ध में उतारने के काबिल नहीं है. अगर इस बात में वाकई तथ्य है तब डीआरडीओ की इतने बरसों की मेहनत पानी में चली गई, यह कहना गलत न होगा. लेकिन सिर्फ डीआरडीओ को दोष देना सही नहीं होगा, आखिर जैसे-जैसे अर्जुन मार्क-1 का विकास

हुआ, तब सेना ने उसका परीक्षण किया और सभी जरूरी बदलाव को उसमें सम्मिलित करने की गुहार लगाई थी. इसकी पूर्ति के बाद ही 122 टैंकों की पहली खेप सेना की 43 और 75 आर्म्ड रेजिमेंट में पहुंचाई गई थी.

वैसे अर्जुन टैंक के इतिहास को देखें तो इस बात का जिक्र है कि मार्च 2010 में अर्जुन ने रूसी डिजाइन के टी-90 को बीकानेर के रेतीले इलाके और चांदमारी के पटल पर पछाड़ा था. इसके बावजूद सेना के कुछ मुद्दे अर्जुन के विरोध में ऊंची आवाज में सुनाई पड़ते हैं - सबसे पहले वजन को लें. 62 टन कुछ ज्यादा ही है जिससे इसके रेगिस्तानी इलाके में धंसने की पूरी-पूरी गुंजाइश बनती है. दूसरे, इसको सरहद तक ले जाने के रास्ते में आने वाली पुलिया और अन्य पुल कमजोर साबित होंगे, साथ ही रेल से इसे ले जाने में दिक्कत आएगी. साथ ही दुश्मन के इलाके में इसे आगे ले जाने में और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा - क्योंकि यहां की पुलिया तो हम बेहतर कर सकते हैं पर सीमा से आगे क्या? जब सेना ने इसकी पुनर्रचना की दरख्वास्त की और 73 बिंदुओं पर दोबारा विचार करने के लिए कहा तब इस टैंक का वजन और बढ़ गया. फिर इसमें लगाए गए बख्तरबंद कवच में कमी पाई गई और लोहा लगाने से इसका वजन 1.5 टन और बढ़ गया.

सेना एक उच्च दर्जे का मुख्य युद्धक टैंक - एमबीटी दोबारा चाह रही है जो रूसी आर्माटा से भी बेहतर हो और चीनी एमबीटी 3000 से एक कदम आगे! सोच अब 2025 तक पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है तब तक क्या? 40 साल के अर्जुन से क्या हम कुछ सीख नहीं पाए? ■■

तोल बोल

लालूप्रसाद यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं. इसीलिए उनके संदर्भ में जेल को सुधार गृह कहना ठीक नहीं है.

■ सुशील कुमार मोदी, भाजपा नेता

चाहे फिल्म हो, रंगमंच या फिर छोटा पर्दा, अच्छे लेखक न हों तो मनोरंजन के ये सभी माध्यम बेकार हैं.

■ अनिल कपूर, फिल्म अभिनेता

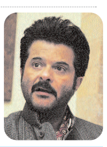

इतिहास पर नजर 12 अगस्त

आज ही के दिन 1985 में जापान एयरलाइन का एक विशाल विमान राजधानी टोकियो से 70 मील दूर ओसूटाका पर्वत से जा टकराया था. विमान पर चालक दल के 15 सदस्यों के साथ 509 यात्री सवार थे. इनमें से ज्यादातर लोग टोकियो से ओसाका छुट्टियां मनाने जा रहे थे. इस हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा था. उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया था कि विमान का पिछला दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है और वो टोकियो लौटकर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं. लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्होंने दोबारा सूचित किया कि विमान पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है. इसके बाद ही विमान रडार स्क्रीन से ओझल हो गया था. दो महीनों में बोइंग 747 के साथ हुआ ये दूसरा हादसा था. 1985 के जून महीने में एयर इंडिया का बोइंग विमान दक्षिणी आयरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे. ■■

- ■1549-फ्रांसीसी सेनाओं ने इंग्लैंड के एंबलटीज पर कब्जा किया.
- ■1831-हॉलैंड और बेल्जियम के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर.
- ■1914-ब्रिटेन ने आस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.
- ■1919-परमाणु वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म.
- ■1940-हॉलैंड ने कपड़े का वितरण नियंत्रित करना शुरू किया.
- ■1953-सोवियत संघ ने पहले हाइड्रोजन बम का गुप्त तरीके से परीक्षण किया.

पाठकों के पत्र

संसद की कार्यवाही चलना जरूरी

संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी. उनका कहना था पहले दोषी मंत्री इस्तीफा दें फिर संसद की कार्यवाही चलने देंगे. ऐसा कब तक चलेगा. इसके पहले जो पक्ष में थे वे आज विपक्ष में हैं. जो विपक्ष में थे वे आज पक्ष में हैं. जिन्होंने पहले लोकसभा की कार्यवाही चलने नहीं दी अब वे सरकार में हैं. संसद सदस्यों को जनता चुनती है ताकि वे लोकसभा में उनकी समस्या रख सकें और उसका निवारण कर सकें. लेकिन ये सदस्य सत्र चलने नहीं देते.

■ प्रमोद शुक्ला, नागपुर

सस्ती दवाएं मिलें

कहा जाता है कि दवा व्यापार में बेहिसाब मुनाफा है जिसका बंटवारा जगह-जगह होता है. इसीलिए दवा लॉबी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी नहीं होने देती. सरकार को दवाएं सस्ती करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा. आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि महंगी दवाएं गरीब लोग खरीद नहीं सकते. आखिर स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है.

■ राघव 'अश्क', बुरहानपुर

आप भी अपने पत्र हमें lsedit.ngp@lokmat.com पर मेल कर सकते हैं या डाक पते पर भेज सकते हैं.

मालिक होने का भ्रम

एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठा हुआ बाजार से गुजर रहा था. बाजार में बहुत से लोग खड़े थे. गधा तेजी से भागा जा रहा था. लोगों ने पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन, कहां भागे जा रहे हो इतनी तेजी से?

हास्य

नसरुद्दीन ने कहा, मुझसे मत पूछो, इस गधे से पूछो. क्योंकि इसका मालिक रहना हो तो इसका अनुयायी रहना पड़ता है. अगर जरा भी मैंने इसको मोड़ने-माड़ने की कोशिश की कि यह अकड़कर खड़ा हो जाता है. उसी वक्त पता चल जाता है बीच बाजार में, कि मालिक हम नहीं हैं. और बेइज्जती होती है, फजीहत हो जाती है. तो मैं समझ गया हूं कि बाजार से जब भी निकलो, जहां यह जाए, बस बैठे रहो. बाजार के बाहर मैं इसे साधने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन बाजार में कभी कोशिश नहीं करता; क्योंकि वहां यह फजीहत करवा देता है, अकड़कर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, लोटने लगता है. वहां पक्का पता चल जाता है कि कौन ताकतवर है. बहुत अनुभव से मैंने यह सीख लिया है कि जिस तरफ यह जाए वही अपनी मंजिल है. कम से कम उसमें हम गधे के मालिक तो मालूम होते हैं. ■■

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XSm
M`a_Z, E[SQm{a`b ~mS : {dO` XSm
E{SQa-BZ-Mr\$: amOÐ XSm
gnmXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Am. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$` Xm{`Ed H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_Jr H$m gdm{YH$ma bmH$_V r{S`m àm`dQ {b. H$ nmg ga{jV h.
bmH$_V _r{S`m àm`dQ {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmH$_V _r{S`m àm. {b., ßbmQ H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S r. gr. BYS{ñQ`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJna _{ÐV Ed bmH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê$ _mJ, ZmJna _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \$Šg : 6618555
Email : gnmXH$` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com